

बेहतर रिश्तों की मुहिम

भारतीय और अमेरिकी नागरिक एक-दूसरे के संगीत, भाषाओं, इतिहास, संस्कृति, समाज और कला की जानकारी हासिल कर आपसी रिश्ता कायम कर रहे हैं। वे एक-दूसरे देश में बने उत्पादों को खरीद कर, एक-दूसरे के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर, अध्यापन और यात्राओं के जरिये, जरूरत के समय मदद और रोगों तथा आपदाओं के मुकाबले के लिए साथ-साथ काम कर भी इस रिश्ते को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। स्पैन के इस अंक में दोनों देशों के बीच इन संपर्कों पर रोशनी डाली गई है। हमने शुरूआत की है स्पैन के प्रकाशक माइकल एच. एंडरसन के विदाई साक्षात्कार से। एंडरसन ने अमेरिकी दूतावास के पब्लिक अफेयर्स अनुभाग के मिनिस्टर काउंसलर के रूप में दोनों देशों के बीच आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयास किए। पत्रकार और अध्यापक के रूप में काम कर चुके एंडरसन अमेरिकी विदेश सेवा में 25 साल बिता चुके हैं और अब वह जकार्ता, इंडोनेशिया में अमेरिकी दूतावास में कार्यभार संभालने जा रहे हैं।

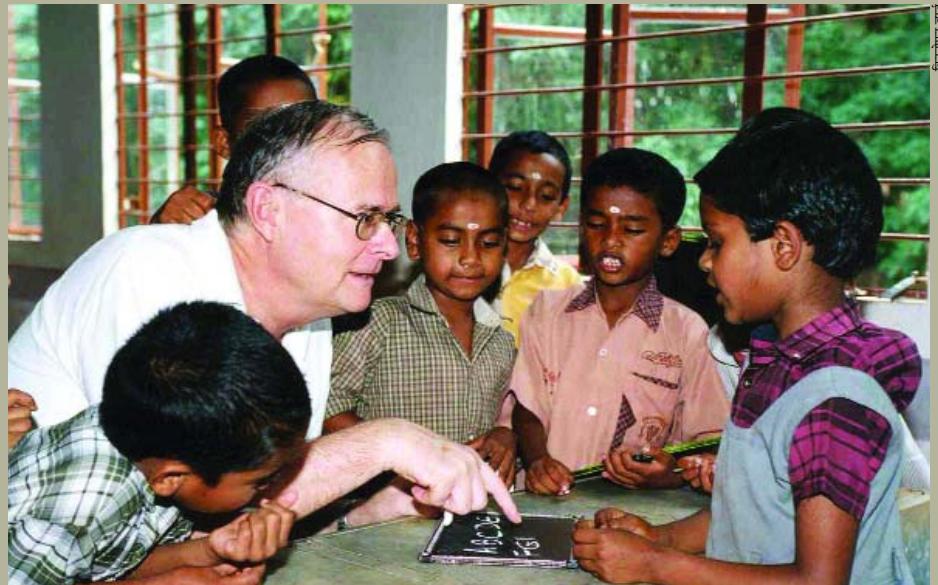
चार साल तक दूतावास में भारतीय प्रेस, सांस्कृतिक और शैक्षणिक मामलों के प्रमुख रहने के बाद भारत-अमेरिकी संबंधों के बारे में आप क्या कहेंगे?

भारत में काम कर रहे बहुत से अमेरिकी राजनयिकों की ही तरह मुझे भी इस अद्भुत देश में दो बार काम करने का अवसर मिला है। वर्ष 1987-90 तक मैं दूतावास का प्रवक्ता/सूचना अधिकारी रहा। फिर वर्ष 2002 में उदारीकरण के दौर के बाद के 'नए' भारत में काम करने के लिए लौटा। हमारे देशों के बीच इतने अच्छे संबंध कभी नहीं रहे। रक्षामंत्री कोंडालीजा राइस ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा है : "भारत अमेरिका का अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा साझेदार है और 21वीं सदी में उसके एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का हम स्वागत करते हैं।"

दोनों देशों की सरकारें और दोनों देशों के अधिकाधिक लोग इस बात को समझने लगे हैं कि एक रणनीतिक साझेदारी विकसित होने में दोनों ही देशों का फायदा है। यही कारण है कि मार्च में राष्ट्रपति बुश भारत की ऐतिहासिक यात्रा पर आए और हमारे बीच सहयोग में इतनी तेजी आई है। भारतीय और अमेरिकी लोगों के बीच सिर्फ परमाणु मुद्दों पर ही नहीं, व्यापार, सुरक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा गतिविधियों के एक बहुत व्यापक क्षेत्र में जबर्दस्त संवाद चल रहा है। दो महान बहुसांस्कृतिक लोकतंत्रों के रूप में हम जान रहे हैं कि इस दौर की बड़ी चुनौतियों-आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और पूंजी निवेश, ऊर्जा, पर्यावरण, एचआइवी/एडीस, मानव तस्करी, संयुक्त राष्ट्र सुधार और अन्य सरोकारों पर अंतरंग सहयोग में हम दोनों का ही हित है।

भारत में किसी कारण आप हताश हुए?

व्यक्तिगत रूप से तो नहीं लेकिन एक राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के बीच



माइकल एंडरसन मार्च 2005 में अलुवा, केरल के जनसेवा शिशु भवन में ऐसे बच्चों के साथ जिन्हें भटकाव की दुनिया से मुक्त कराया गया।

अधिक संपर्क के हामी के तौर पर कुछ हताशा हुई तो है। उदाहरण के लिए, मैं चाहूंगा कि दोनों देशों के बीच और अधिक शैक्षिक सहयोग हो जिससे दोनों देशों को एक बदलते संसार से तालमेल बैठाने में मदद मिले। चोटी के, बीसियों अमेरिकी विश्वविद्यालय भारत के साथ काम करने को व्यग्र हैं लेकिन फिलहाल इसके लिए अवसर हैं ही नहीं, शैक्षणिक आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए नीतियां नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार जल्द ही संयुक्त शोध और अन्य भारतीय-अमेरिकी शैक्षणिक सहयोग और शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने वाली स्पष्ट नीतियां लागू कर लेगी। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में किसी भी अन्य देश की अपेक्षा भारत के छात्र अधिक हैं- पिछले साल इनकी संख्या 80,466 थी। जरूरत इस बात की है कि इस असंतुलन को

कम करने के लिए अधिक संख्या में अमेरिकी अध्येताओं का भारत आकर अध्ययन कर पाना संभव बनाया जाए।

अमेरिकी अध्येताओं को आकर्षित करने के लिए भारत को विशिष्ट रूप से क्या करना होगा?

शोध की अनुमति और वीजा जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन जैसे संगठन और भारतीय विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत में मौजूद अवसरों को अमेरिका में अधिक सक्रियता से प्रचारित करें। अधिक संख्या में विदेशी छात्रों-अध्येताओं को आकर्षित करने के लिए छात्रावासों, कैटीनों, प्रकाशनों, वेबसाइटों, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में काफी सुधार की गुंजाइश है। भारत में अध्ययन करने के लिए अमेरिकी छात्र तो जरूर ही पैसा खर्च करना चाहेंगे लेकिन आधारभूत

ढांचे में सुधार और एकदम स्पष्ट और उत्साहवद्धक नीतियां न हों तो उनकी संख्या सीमित ही रहने वाली है। आज जब बहुत से देश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से सुधार लाकर उसे विश्वस्तरीय बनाने की ओर अग्रसर हैं तब भारत ज़िज़कता और अस्पष्ट संकेत भेजता दिख रहा है।

भारतीय विश्वविद्यालयों में तो वैसे ही सीटें कम हैं तो भारत विदेशी छात्रों को बुलाने की कोशिश ही क्यों करे?

वैश्विक स्तर पर होड़ में शामिल हो पाने के लिए जरूरी है कि भारत संसार के 'सबसे बढ़िया, सबसे तेज' छात्रों को आकर्षित करे और संसारभर के जानेमाने शैक्षिक संस्थानों के साथ विचारों और शोध का आदान-प्रदान करे। अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा से आपसी समझदारी और नए ज्ञान को ही प्रोत्साहन नहीं मिलता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार, कृषि, सामाजिक विज्ञान और उन अन्य क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन मिलता है जिनसे लोगों के जीवनों को सुधारने और एक ज्ञान-आधारित, अधिक आधुनिक अर्थतंत्र के विकास में भी सहायता मिलती है। हमारे विश्वविद्यालयों के बीच कई बढ़िया चीजें हो रही हैं जैसे राष्ट्रपति बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई कृषि ज्ञान पहल। लेकिन इससे कहीं अधिक चीजें की जा सकती हैं और की जानी चाहिए। हमारे द्विपक्षीय शैक्षणिक सहयोग की शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कि यही वक्त है जब निजी और सार्वजनिक भारतीय और अमेरिकी विश्वविद्यालयों के बीच तमाम तरह की साझेदारियां विकसित और विस्तारित हो सकती हैं। भारत को शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध सेवाओं का आयात और निर्यात, दोनों करना चाहिए। इसकी जरूरत मौजूद है और बढ़ भी रही है और सभी जगह विद्वानों-शिक्षकों का आवागमन बढ़ रहा है।

भारतीय मीडिया से संपर्क आपके काम का काफी बड़ा हिस्सा रहा। आप उसके प्रदर्शन को कैसे देखते-समझते हैं?

अमेरिकी प्रेस की ही तरह भारतीय प्रेस भी जीवंत और स्वतंत्र है। उसमें छपी चीजों से मेरी असहमति अक्सर बनी रही लेकिन मैं उसकी आजादी का सम्मान करता हूँ। मैंने देखा कि प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है, खासतौर पर उत्पाद की गुणवत्ता में तो पिछले कुछ वर्षों में खासा सुधार आया है। अमेरिकी मीडिया के विपरीत, भारतीय मीडिया भाग्यशाली है कि वह विकास के दौर में है और यह स्पष्ट दिखता है- जहां देखिए नए चैनल, एफएम स्टेशन, नए प्रकाशन, विद्याएं और ऑनलाइन सेवाएं शुरू हो रही हैं। अमेरिका में तो पत्रकार इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि

खबरों और मनोरंजन के स्रोतों के तौर पर केबल टीवी और इंटरनेट की लगातार बढ़ती भूमिका के चलते दैनिक अखबार और यहां तक कि हमारे चार महत्वपूर्ण प्रसारण नेटवर्क भी अंततः अप्रसंगिक हो सकते हैं। मुझे जो बात जरा परेशान करती है वह है भारतीय प्रेस के एक हिस्से का बेहद सनसनीखेज और हद से ज्यादा 'पेज थ्री' प्रेमी हो जाना। अमेरिका में भी यही होता दिख रहा है।

मैं सोचता हूँ कि जिम्मेदार नागरिकों के तौर पर हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चे पढ़ने की आदत डालें और समसामयिक घटनाक्रम की जानकारी रखें। सिकुड़ती जा रही दुनिया में यह और भी जरूरी है क्योंकि भारत में जो होता है उसका असर अमेरिका पर पड़ता है, जो अमेरिका में होता है उसका भारत पर। वॉल स्ट्रीट हो या दलाल स्ट्रीट, हॉलीवुड या बॉलीवुड, तेल के दाम हों या गेहूँ के, देशों की अंतर्निर्भरता बढ़ रही है और अपने लोकतंत्रों को बनाए रखने, शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जरूरी है कि हमें

लगता है कि इसके लागू होने से औसत भारतीय नागरिक का जबरदस्त सशक्तीकरण होगा और सरकार अधिक पारदर्शी और संवेदनशील बनेगी।

भारत में मौजूद अमेरिकन सेंटरों में क्या हो रहा है?

नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई स्थित अमेरिकन सेंटर सक्रिय रूप से "पब्लिक डिप्लोमेसी" गतिविधियों में जुटे हैं- वे अमेरिकी नीतियों और मूल्यों और बहुरंगी-बहुविध अमेरिकी समाज के बारे में अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दे रहे हैं और भारतीय समाज के एक अधिक बड़े हिस्से से संपर्क बना रहे हैं। हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वक्ताओं, फिल्मों, कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से यह काम करते हैं और अक्सर भारतीय संगठन हमारे सहयोगी होते हैं। हम एचआइवी/एड्स, पर्यावरण की सुरक्षा, आर्थिक सुधार, परमाणु प्रसार और जैवप्रौद्योगिकी जैसे विविध समसामयिक विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। भारत की जनसंख्या का आधे से अधिक



सामर: एमिटी इंटरनेशनल स्कूल

नई दिल्ली में साकेत स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र सात्विक अग्रवाल को बधाई देते माइकल एंडरसन। सात्विक को नवंबर 2003 में नासा की मंगल खोज परियोजना के तहत कैलिफोर्निया की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला में काम करने के लिए चुना गया। हाल ही में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने सत्विक को अपने यहां पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी है।

हमेशा पूरी सूचनाएं उपलब्ध हों। भारत में हाल ही में घटी जिस घटना से मैं बहुत प्रभवित हुआ वह सूचना अधिकार विधेयक का पारित होना है। अमेरिका के फ्रीडम ऑफ इनफॉर्मेशन एक्ट की तर्ज पर बने इस कानून के दूरगामी प्रभाव होंगे। मुझे

हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु वर्ग में है। हम युवा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। स्पैन के हिंदी और उर्दू संस्करणों के माध्यम से हम गैर-अंग्रेजीभाषी वर्ग के पाठकों से बेहतर संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सार्वजनिक पुस्तकालय अब अमेरिकी सूचना संसाधन केंद्र कहे जाते हैं। हाल ही में हमने अंग्रेजी पढ़ाने के एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। फुल्ब्राइट और अन्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने और छात्रों को अमेरिका में उच्च अध्ययन में सहायता के लिए सलाहकार सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु हम यू.एस. एजुकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया (यूसेफी) के साथ मिलकर काम करते हैं। □